RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 176
दि. 31.03.2026, मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

आधे सदी का अंत: लाल गलियारे की हिंसा पर निर्णायक प्रहार, 2026 तक नक्सलवाद लगभग समाप्त होने का दावा

नई दिल्ली। भारत की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में एक ऐसा मोड़ सामने आया है, जिसे एक लंबे और हिंसक अध्याय के समापन के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 1970 के दशक से देश के लिए चुनौती बने नक्सलवाद का प्रभाव अब लगभग समाप्ति की कगार पर है और 31 मार्च 2026 इस संघर्ष के अंत का प्रतीक बनकर उभरेगा। दशकों तक नेपाल के पशुपति क्षेत्र से लेकर दक्षिण में आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक फैले तथाकथित 'लाल गलियारे' ने जिस तरह देश की आंतरिक सुरक्षा, विकास और सामाजिक संतुलन को प्रभावित किया, वह अब तेजी से सिमटकर लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया है। यह परिवर्तन केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई का परिणाम नहीं, बल्कि एक समन्वित रणनीति का असर है, जिसमें सुरक्षा, विकास और विश्वास को एक साथ केंद्र में रखा गया। सरकारी आंकड़े इस बदलाव की गवाही देते हैं। वर्ष 2014 में जहां देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित माने जाते थे और 35 जिले अति संवेदनशील श्रेणी में आते थे, वहीं 2026 तक यह संख्या घटकर मात्र 2 जिलों तक सीमित रह गई है। इसी तरह, 350 ऐसे पुलिस स्टेशन जहां नियमित रूप से नक्सली घटनाएं दर्ज होती थीं, उनकी संख्या घटकर केवल 7 रह गई है। इन आंकड़ों को सरकार अपनी नीति की सफलता के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जो यह संकेत देते हैं कि नक्सलवाद का भौगोलिक और संचालनात्मक दायरा अब बेहद सीमित हो चुका है।

नक्सलवाद की जड़ें भारत के वामपंथी राजनीतिक इतिहास के उस दौर से जुड़ी हैं, जब 1964 में वैचारिक मतभेदों के चलते कम्युनिस्ट आंदोलन दो हिस्सों में बंट गया था। इसके बाद 1969 में भाकपा (माले) के गठन के साथ एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने संसदीय लोकतंत्र को नकारते हुए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। पश्चिम बंगाल के Naxalbari से शुरू हुआ यह आंदोलन धीरे-धीरे उन क्षेत्रों में फैलता गया, जहां शासन-प्रशासन की पहुंच कमजोर थी और आदिवासी तथा ग्रामीण समुदाय विकास से वंचित थे। 1975 के बाद माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) और 1990 के दशक में पीपुल्स वॉर ग्रुप जैसे संगठनों के उभार ने इस आंदोलन को और मजबूत किया। वर्ष 2004 में विभिन्न माओवादी गुटों के विलय के बाद यह नेटवर्क और संगठित हो गया, जिससे 'रेड कॉरिडोर' का विस्तार देश के कई राज्यों में हो गया।

गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत टाइमलाइन प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह आंदोलन मूल रूप से विकास के लिए नहीं, बल्कि सत्ता हासिल करने की सोच से प्रेरित था। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलियों ने उन इलाकों को चुना जहां प्रशासनिक ढांचा कमजोर था और स्थानीय आबादी को गुमराह कर उन्हें हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया गया। लंबे समय तक यह समस्या केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा मानी जाती रही, लेकिन इसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।

वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। केवल सैन्य कार्रवाई के बजाय एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई के साथ-साथ विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया गया। सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही, स्थानीय समुदायों का विश्वास जीतने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गईं। इस त्रिस्तरीय रणनीति—सुरक्षा, विकास और विश्वास—ने धीरे-धीरे नक्सली नेटवर्क को कमजोर कर दिया।

लोकसभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा के दौरान Asaduddin Owaisi, Kangana Ranaut और Anurag Thakur समेत कई नेताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि आदिवासी समाज लंबे समय से चाहता था कि उनकी समस्याओं को संसद में गंभीरता से उठाया जाए, लेकिन दशकों तक ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब हालात बदल रहे हैं और जिन क्षेत्रों में कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, वहां अब विकास की रफ्तार दिखाई दे रही है।

हालांकि, विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि किसी भी विचारधारात्मक आंदोलन का पूरी तरह समाप्त होना केवल सुरक्षा उपायों से संभव नहीं होता। इसके लिए सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और समावेशी विकास की प्रक्रिया को लगातार जारी रखना जरूरी है। इसके बावजूद, हिंसा में आई भारी कमी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के तेजी से सामान्य होते हालात इस बात का संकेत हैं कि भारत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है।

कुल मिलाकर, 'लाल गलियारे' का यह कथित सूर्यास्त केवल एक सुरक्षा उपलब्धि नहीं, बल्कि उस व्यापक परिवर्तन का प्रतीक है जिसमें देश ने एक लंबे संघर्ष के बाद स्थिरता और विकास की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया है। यदि यह रफ्तार बनी रहती है, तो आने वाले समय में भारत वास्तव में नक्सलवाद मुक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर सकता है।

मनरेगा पर सियासी संग्राम: मजदूरों की रोजी-रोटी पर संकट का आरोप, सरकार की नीतियों पर खरगे का तीखा प्रहार

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर एक बार फिर सियासी माहौल गर्म हो गया है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मनरेगा को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है और इससे करोड़ों मजदूरों की आजीविका खतरे में पड़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने न केवल मनरेगा के तहत मिलने वाले काम के अधिकार को सीमित कर दिया है, बल्कि इसके स्थान पर लाई गई नई योजनाएं भी जमीनी स्तर पर पूरी तरह विफल साबित हो रही हैं। उनके अनुसार, यह केवल नीतिगत बदलाव नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों के जीवन पर सीधा असर डालने वाला फैसला है।

खरगे ने अपने बयान में यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान जब देशभर में रोजगार के अवसर खत्म हो गए थे, उस समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNREGA ने लाखों-करोड़ों मजदूरों को सहारा दिया था। गांवों में लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना जीवनरेखा साबित हुई थी, जिसने उन्हें न्यूनतम आय और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर दिया। लेकिन आज वही योजना कथित रूप से संसाधनों की कमी, काम की अनुपलब्धता और प्रशासनिक उदासीनता के कारण कमजोर होती जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

उन्होंने विशेष रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां पिछले करीब 87 दिनों से 12 हजार मजदूर काम न मिलने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी मनरेगा के काम ठप होने या धीमे पड़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं। खरगे के अनुसार, कुछ स्थानों पर तो अधिकारियों को नए काम शुरू न करने के निर्देश तक दिए जाने की बातें सामने आई हैं, जो इस योजना के मूल उद्देश्य के विपरीत है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता और बढ़ सकती है।

कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित तथाकथित नई योजना—VBG Ramji Scheme—पर भी सवाल उठाए हैं। खरगे का कहना है कि 21 दिसंबर 2025 को अधिसूचित इस योजना का जमीनी स्तर पर कोई ठोस असर दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस योजना का बड़े पैमाने पर प्रचार तो किया, लेकिन मजदूरों तक इसका लाभ पहुंचाने में पूरी तरह असफल रही है। उनके अनुसार, जब पुरानी और प्रभावी योजना को कमजोर किया जा रहा है, तो नई योजना का प्रभावी क्रियान्वयन न होना सरकार की नीतिगत विफलता को दर्शाता है।

उन्होंने महाराष्ट्र की कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी कहा कि पिछले पांच वर्षों में मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों में से 53 प्रतिशत से भी कम पूरे हो पाए हैं, जबकि लगभग ढाई लाख कार्य ऐसे हैं जो शुरू ही नहीं हो सके। यह आंकड़े न केवल योजना के क्रियान्वयन में खामियों की ओर इशारा करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर कहीं न कहीं गंभीर कमी मौजूद है। यदि योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाएं और उनका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक न पहुंचे, तो उनका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती जा रही है। जहां विपक्ष इसे गरीबों और मजदूरों के अधिकारों पर हमला बता रहा है, वहीं सरकार की ओर से अब तक इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन यह स्पष्ट है कि मनरेगा जैसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पर उठे सवाल आने वाले समय में राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर गूंजते रहेंगे।

कुल मिलाकर, यह विवाद केवल एक योजना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक बहस का हिस्सा है जिसमें यह तय होना है कि देश के ग्रामीण और श्रमिक वर्ग को किस प्रकार की सुरक्षा और समर्थन दिया जाना चाहिए। यदि मनरेगा जैसी योजनाएं कमजोर पड़ती हैं, तो इसका असर केवल मजदूरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे ग्रामीण तंत्र और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।

नए वित्त वर्ष का असर: हाईवे पर सफर हुआ महंगा, टोल दरों में बढ़ोतरी से आम आदमी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर बढ़ेगा बोझ

नई दिल्ली। नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत आम लोगों के लिए एक और आर्थिक दबाव लेकर आई है, जहां एक अप्रैल से देशभर के नेशनल हाईवे पर सफर करना पहले की तुलना में महंगा हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा टोल टैक्स की दरों में लगभग 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का फैसला लागू कर दिया गया है, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले लाखों लोगों, निजी वाहन चालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। यह बढ़ोतरी हर साल की तरह इस बार भी वार्षिक समीक्षा के आधार पर की गई है, लेकिन महंगाई के मौजूदा दौर में इसका प्रभाव और अधिक महसूस किया जाएगा।

टोल टैक्स में इस वृद्धि के साथ ही निजी वाहनों के लिए उपलब्ध वार्षिक पास भी महंगा कर दिया गया है। पहले 3000 रुपये में मिलने वाला यह पास, जिसमें 200 यात्राओं की सुविधा दी जाती थी, अब 75 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया है। यह बदलाव खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो रोजाना कामकाज, नौकरी या व्यापार के सिलसिले में हाईवे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह अतिरिक्त खर्च धीरे-धीरे एक बड़े आर्थिक बोझ में बदल सकता है। छोटे व्यापारियों, टैक्सी चालकों, बस ऑपरेटरों और माल ढुलाई से जुड़े लोगों के लिए यह बढ़ोतरी लागत में इजाफा करेगी, जिसका असर आगे चलकर आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंच सकता है।

सरकार और संबंधित अधिकारियों का कहना है कि टोल दरों में यह वृद्धि सड़क के रखरखाव, मरम्मत और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। देशभर में तेजी से विकसित हो रहे हाईवे नेटवर्क, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार निवेश की आवश्यकता होती है, और टोल से मिलने वाला राजस्व इसी दिशा में उपयोग किया जाता है। हालांकि, आम जनता के नजरिए से देखें तो यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पहले से ही ईंधन, खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बना हुआ है।

विशेषज्ञों का मानना है कि टोल टैक्स में बढ़ोतरी का प्रभाव केवल यात्रा खर्च तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह देश की सप्लाई चेन और बाजार व्यवस्था पर भी असर डालेगा। जब परिवहन लागत बढ़ती है, तो उसका सीधा असर वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है, जिससे महंगाई में और इजाफा हो सकता है। ऐसे में यह फैसला आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न स्तरों पर प्रभाव डाल सकता है।

कुल मिलाकर, एक अप्रैल से लागू हुई टोल दरों में वृद्धि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बेहतर सड़क सुविधाओं की कीमत अब आम नागरिकों को अधिक चुकानी पड़ेगी। जहां एक ओर यह कदम इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए जरूरी बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आम जनता के लिए यह एक नई आर्थिक चुनौती के रूप में सामने आया है, जिसका असर आने वाले समय में और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

साइको चोर का आतंक: महिलाओं के अंतर्वस्त्र बना निशाना, रहस्यमयी वारदातों से दहशत में शहर, पुलिस के सामने बड़ी चुनौती

बंगलूरू। कर्नाटक के Koppal district के Gangavathi शहर में इन दिनों एक ऐसी अजीबोगरीब और चिंताजनक घटनाओं की श्रृंखला सामने आ रही है, जिसने न केवल स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है बल्कि पूरे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा कर दिया है। यहां एक अज्ञात व्यक्ति, जिसे लोग 'साइको चोर' के नाम से पहचानने लगे हैं, लगातार घरों में घुसकर केवल महिलाओं के अंतर्वस्त्रों की चोरी कर रहा है। यह घटनाएं सामान्य चोरी से बिल्कुल अलग हैं और इसी कारण यह मामला पुलिस और समाज दोनों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है।

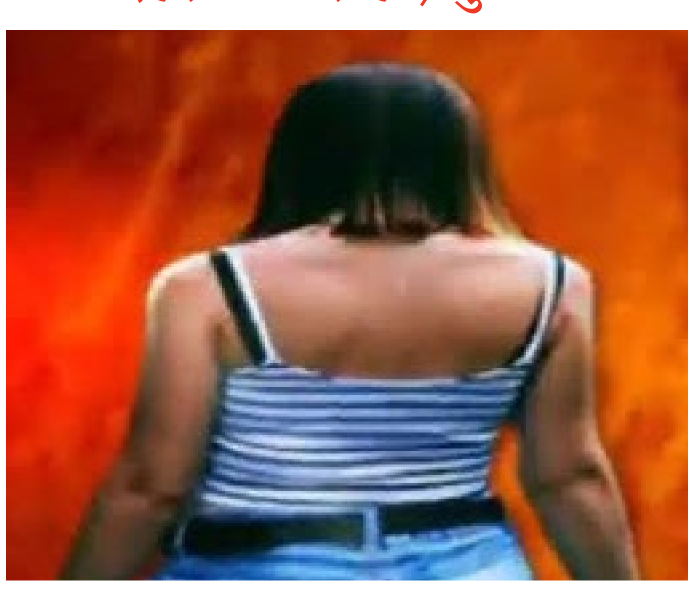

जानकारी के अनुसार, यह रहस्यमयी चोर देर रात ऐसे समय को चुनता है जब लोग गहरी नींद में होते हैं और आसपास का माहौल पूरी तरह शांत होता है। वह बेहद चुपचाप घरों की दीवारों को फांदकर अंदर प्रवेश करता है और सीधे उन स्थानों की ओर जाता है जहां कपड़े सुखाने के लिए डाले जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वह किसी भी अन्य कीमती सामान को हाथ नहीं लगाता, बल्कि केवल महिलाओं के अंडरगारमेंट्स को ही चुनकर अपने साथ ले जाता है और कुछ ही मिनटों में मौके से फरार हो जाता है। उसकी यह हरकतें यह संकेत देती हैं कि यह कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि किसी विकृत मानसिकता से प्रेरित व्यक्ति हो सकता है।

इस पूरे मामले में सबसे अहम मोड़ तब आया जब इलाके के कई घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में यह शख्स कैद हो गया। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि वह संदिग्ध व्यक्ति बेहद सतर्कता और तेजी के साथ दीवार फांदकर अंदर घुसता है, इधर-उधर नजर दौड़ाता है और फिर चोरी को अंजाम देकर तुरंत भाग निकलता है। उसकी चाल-ढाल और हरकतें यह दर्शाती हैं कि वह पहले से इलाके की रेकी कर चुका है और उसे यह अच्छी तरह पता है कि कहां और कब जाना है।

पिछले तीन से चार दिनों के भीतर इस तरह की कई घटनाएं सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल गहराता जा रहा है। खासकर महिलाओं में इस घटना को लेकर गहरी चिंता और असुरक्षा की भावना देखी जा रही है। उनका कहना है कि यह केवल चोरी नहीं है, बल्कि उनकी निजी जिंदगी और सम्मान से जुड़ा मामला है। कई महिलाओं ने अब रात के समय बाहर कपड़े सुखाना बंद कर दिया है, वहीं कुछ परिवारों ने अपने घरों में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जैसे नए ताले, ग्रिल और कैमरे लगवाने शुरू कर दिए हैं।

स्थानीय निवासियों का मानना है कि इस तरह की हरकतें किसी मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति की ओर इशारा करती हैं। लोगों ने इसे केवल कानून-व्यवस्था का मामला न मानते हुए एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में भी देखा है। कई लोगों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच कराई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

पुलिस के लिए भी यह मामला चुनौतीपूर्ण बन गया है, क्योंकि यहां चोरी का उद्देश्य पारंपरिक नहीं है। आमतौर पर चोर पैसे, गहने या अन्य कीमती सामान को निशाना बनाते हैं, लेकिन इस मामले में केवल महिलाओं के अंतर्वस्त्रों को ही टारगेट किया जा रहा है। इससे यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही, आसपास के क्षेत्रों में भी अलर्ट जारी किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी कहीं और इस तरह की वारदात को अंजाम न दे सके।

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि वे अपने घरों के आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें। साथ ही, रात के समय दरवाजों और खिड़कियों को अच्छी तरह बंद रखने और कपड़ों को खुले में न छोड़ने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने के लिए कहा गया है।

यह पूरा मामला केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में सुरक्षा, निजता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भी उजागर करता है। जिस तरह से एक अज्ञात व्यक्ति लगातार महिलाओं को निशाना बना रहा है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक तकनीक और सुरक्षा उपायों के बावजूद भी कुछ खतरे ऐसे हैं जो अप्रत्याशित और असामान्य होते हैं।

अब पूरे इलाके की नजर पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस 'साइको चोर' को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस अजीबोगरीब आतंक से उन्हें राहत मिलेगी। तब तक, Gangavathi के लोग सतर्कता और सावधानी के सहारे ही इस अनिश्चित डर के बीच अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने को मजबूर हैं।

संपादकीय

तकनीकी निर्भरता घटा रही कुदरती क्षमता

आज का मनुष्य तकनीक के ऐसे दौर में जी रहा है जहां हर समस्या का समाधान कुछ ही सेकंड में मिल जाता है। स्मार्टफोन, इंटरनेट और जीपीएस जैसी सुविधाओं ने जीवन को बेहद आसान बना दिया है। लेकिन इस सुविधा की एक कीमत भी है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह कीमत है—हमारी प्राकृतिक मानसिक क्षमताओं का धीरे-धीरे कमजोर होना। विशेष रूप से दिशा पहचानने और रास्ते याद रखने की क्षमता, जो कभी मनुष्य की एक महत्वपूर्ण ताकत हुआ करती थी, अब तकनीक के कारण कमजोर पड़ती जा रही है। प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. एडवर्ड मोजर ने इस विषय पर चिंता जताते हुए कहा है कि जीपीएस पर बढ़ती निर्भरता मानव मस्तिष्क के "कुदरती जीपीएस" को प्रभावित कर रही है। यह कुदरती जीपीएस हमारे मस्तिष्क में मौजूद विशेष कोशिकाओं के माध्यम से काम करता है, जिन्हें "ग्रिड सेल्स" कहा जाता है। ये कोशिकाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम कहां हैं और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। यही प्रणाली हमारे दिमाग में एक मानसिक नक्शा तैयार करती है, जिससे हम अपने आसपास के वातावरण को समझ पाते हैं। कुछ साल पहले तक जब जीपीएस का इतना प्रचलन नहीं था, तब लोग अपने अनुभव और याददाश्त के आधार पर रास्ते तय करते थे। वे सड़कों के मोड़, आसपास की इमारतों, पेड़ों, दुकानों और अन्य संकेतों को ध्यान में रखकर अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। यह प्रक्रिया केवल एक यात्रा नहीं होती थी, बल्कि यह मस्तिष्क के लिए एक अभ्यास भी होती थी, जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ती थी।

आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। हम किसी भी नए स्थान पर जाने से पहले जीपीएस का सहारा लेते हैं और बिना सोचे-समझे उसके निर्देशों का पालन करते हैं। हम यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं या आसपास क्या है। परिणामस्वरूप, हम एक ही रास्ते पर कई बार जाने के बाद भी उसे याद नहीं रख पाते। यह केवल एक आदत नहीं, बल्कि हमारी मानसिक क्षमता में गिरावट का संकेत है। यह समस्या केवल दिशा-बोध तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव हमारी स्मरण शक्ति पर भी पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, पहले लोग अपने परिवार और दोस्तों के कई फोन नंबर याद रखते थे। लेकिन अब हम सभी नंबर मोबाइल में सेव कर लेते हैं और उन्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं समझते। इसी तरह, जीपीएस के कारण हम रास्तों को याद रखने की कोशिश नहीं करते, जिससे हमारी स्मृति कमजोर होती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मस्तिष्क भी एक मांसपेशी की तरह है। यदि इसका नियमित उपयोग किया जाए तो यह मजबूत होता है, और यदि इसे निष्क्रिय छोड़ दिया जाए तो यह कमजोर पड़ने लगता है। जब हम जीपीएस पर निर्भर रहते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क के उस हिस्से का उपयोग नहीं करते जो दिशा पहचानने के लिए जिम्मेदार है। इससे वह हिस्सा धीरे-धीरे कम सक्रिय हो जाता है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें तकनीक का उपयोग पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। जीपीएस एक उपयोगी साधन है, जो हमें अनजान स्थानों पर आसानी से पहुंचने में मदद करता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम पूरी तरह इस पर निर्भर हो जाते हैं और अपनी प्राकृतिक क्षमताओं का उपयोग करना बंद कर देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम तकनीक और अपनी प्राकृतिक क्षमताओं के बीच संतुलन बनाए रखें। हमें समय-समय पर बिना जीपीएस के यात्रा करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम किसी नए स्थान पर जाएं, तो रास्तों को समझने और याद रखने की कोशिश करें। आसपास के वातावरण पर ध्यान दें, महत्वपूर्ण स्थानों को पहचानें और अपने दिमाग में उनका नक्शा बनाने का प्रयास करें। बच्चों के लिए यह और भी जरूरी है। यदि उन्हें बचपन से ही हर काम के लिए तकनीक पर निर्भर रहना सिखाया जाएगा, तो उनकी प्राकृतिक क्षमताएं विकसित नहीं हो पाएंगी। इसलिए उन्हें ऐसे खेल और गतिविधियों में शामिल करना चाहिए, जो उनकी दिशा-बोध और स्मरण शक्ति को विकसित करें।

इसके अलावा, वैज्ञानिक इस दिशा में भी शोध कर रहे हैं कि मानव मस्तिष्क की इस कुदरती जीपीएस प्रणाली को रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कैसे उपयोग किया जा सकता है। यदि इसमें सफलता मिलती है, तो मशीनें भी इंसानों की तरह अपने आसपास के वातावरण को समझकर निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगी। यह दर्शाता है कि हमारा मस्तिष्क कितना उन्नत और प्रेरणादायक है।

अंततः, हमें यह समझना होगा कि तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, न कि हमारी क्षमताओं को खत्म करने के लिए। यदि हम अपनी सुविधाओं के लिए अपनी प्राकृतिक शक्तियों को नजरअंदाज करेंगे, तो एक दिन हम उन क्षमताओं को पूरी तरह खो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जीपीएस का उपयोग समझदारी से करें और अपने मस्तिष्क के कुदरती जीपीएस को भी सक्रिय बनाए रखें। यही संतुलन हमें एक बेहतर और सक्षम इंसान बना सकता है।

वैश्विक संकट के दौर में वैश्विक पर्यटन उद्योग

> "वर्तमान दौर में दुनिया के चौधरी बने देशों को यह समझ लेना चाहिए कि अब वह जमाना गया जब हफ्ते दो हफ्ते में युद्ध का फैसला हो जाया करता था। आज छोटा से छोटा देश भी युद्ध को लंबा खींचने की कुब्बत रखता है। इसे हम रुस यूक्रेन युद्ध से अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के साइड इफेक्ट के रुप में दुनिया का पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 152 करोड़ पर्यटकों से गुलजार रहने वाला वैश्विक पर्यटन उद्योग के वैश्विक हालातों के चलते वर्तमान हालातों में मंदी से भी अतिमंदी के दौर से गुजरने की संभावना से नहीं नकारा जा सकता। वैसे तो सभी देशों में पर्यटन उद्योग पर विपरीत असर पड़ने जा रहा है पर सबसे अधिक असर मध्यपूर्व के देशों में देखा जा सकता है। जानकारों के अनुसार अकेले मध्यपूर्व को ही 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। दुनिया में सबसे अधिक पर्यटक फ्रांस की धरती पर जाते है और माना जाता है कि 9 से 10 करोड़ पर्यटक तो फ्रांस का रुख करते हैं। जहां तक भारत का प्रश्न है हमारे यहां भी लगभग 2 करोड़ विदेशी पर्यटक देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं। पर युद्ध के वैश्विक हालातों के चलते विश्व के अन्य देशों की तरह से भारत के भी विदेशी पर्यटकों की आवाही पर विपरीत प्रभाव पड़ना ही है। एक सकारात्मक पक्ष यह देखा जा सकता है कि भारत और दुनिया के देशों में देशी पर्यटकों की संख्या में उछाल के चलते इस उद्योग को संजीवनी अवश्य मिलती लगती है। वर्तमान दौर में दुनिया के चौधरी बने देशों को यह समझ लेना चाहिए कि अब वह जमाना गया जब हफ्ते दो हफ्ते में युद्ध का फैसला हो जाया करता था। आज छोटा से छोटा देश भी युद्ध को लंबा खींचने की कुब्बत रखता है। इसे हम रुस यूक्रेन युद्ध से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अमेरिका ने भी जब ईरान पर आक्रमण

किया तो ट्रंप का कायास यही था कि दो चार दिन में ईरान के घुटने टिकवा देंगे पर ट्रंप और नेतन्याहू के सारे कयास धरे के धरे रह गए और इनके चक्कर में दुनिया अस्थिरता और वैश्विक संकट में और आ गई। आज हालात यह हो गए हैं कि युद्ध तो आप शुरु कर सकते हो पर युद्ध शुरु होने के बाद कब बंद होगा यह आपके हाथ में नहीं रहेगा। युद्ध के चलते अब हालात ऐसे हो गए है कि चाह कर भी पर्यटक घूमने का रुख नहीं कर पा रहे हैं। केवल और केवल ट्रंप के दादागिरी पूर्ण रवैये के चलते दुनिया की देशों की जीडीपी में करीब 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी निभाने वाला पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। होटल और ट्रेवल उद्योग से जुड़ी एजेंसियां के सामने बड़ा संकट आ गया है तो दुनिया के देशों और संस्कृतियों से जुड़ने और समझ कर एक दूसरे के नजदीक आने की जो पहल पर्यटन उद्योग के चलते हुई थी उस पर लगभग विराम के से हालात होते जा रहे हैं। 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का पर्यटन उद्योग आज संकट के दौर में आ गया है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो थाईलैंड की अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी पर्यटन उद्योग की है और वह लगातार दूसरे साल गंभीर संकट के दौर में आ गई है। जैसे तैसे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हजार डॉलर प्रतिदिन के लग्जरी कमरों की कीमत घटकर 300 डॉलर तक कर देने के बाद भी पर्यटक रुख नहीं कर रहे हैं। हालात विकट से विकटतर होते जा रहे हैं।

दरअसल वैश्विक हालातों के चलते एक और उड़ाने रद्द होती जा रही है तो युद्ध के चलते लोगों में असुरक्षा की भावना होती जा रही है। पता नहीं कब कहां क्या हो जाए और कहीं जाएं वहीं पर बंद होकर के रह जाएं। इस तरह की आशंकाओं से भी दो चार हो रहे हैं। मध्यपूर्व के देशों में तो लगभग यही हालात है। कब किस देश और किस स्थान पर मिसाइल अटैक हो जाएं कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अमेरिका-इजरायल व ईरान युद्ध की खास नकारात्मक बात यह है कि इन दो देशों पर मिसाइल अटैक नहीं हो रहे बल्कि इनसे थोड़ी सी भी सहानुभूति रखने वाले देष कब निशाने पर आ जाएं कहा नहीं जा सकता। मध्यपूर्व में मिसाइल अटैक और हार्मुज जलडमरुमध्य के हालात इसके उदाहरण है। हालात तो यहां तक खराब होने की संभावना से इंकार नहीं करते कि मध्यपूर्व के देषों में तो पानी का गंभीर संकट तो हो सकता है। आज कच्चा तेल, एलपीजी की ही समस्या नहीं अपितु दुनिया को जोड़ने वाले इंटरनेट के बाधित होने की संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। लगता है एक दूसरे के अहम् के चलते आमआदमी कहीं हाशिये में चला गया है। युद्ध के सामान्य नियम भी ताक में रख दिए गए हैं और आमनागरिकों, बच्चों, अस्पतालों, घनी आबादी इलाकों में भी मिसाइल दागने से कोई परहेज नहीं रह गया है।

कोरोना के दौरान जिस तरह से पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ था आज उसी तरह के हालात बनते दिख रहे हैं। कोरोना के बाद पिछले सालों में पर्यटन उद्योग ने तेजी पकड़ी थी और लगने लगा था कि 2030 तक पर्यटन उद्योग को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा पर अब हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई सुधार दिखाई देगा। हांलाकि एक सकारात्मक पक्ष यह देखा जा सकता है कि भारत सहित विश्व के देशों में देशी पर्यटन को अवष्य बढावा मिलने लगा है। लोग अपने ही देश में आसपास के स्थानों को एक्सप्लोर करने लगे हैं। खैर वर्तमान हालात पर्यटन उद्योग के लिए बेहद चुनौती भरे हो गए हैं और सामान्य हालात होने के अभी तो दूर दूर तक आसार ही नहीं दिख रहे हैं।

प्रेरणा

अधिकार की सच्ची रोटीः ईमानदारी का अनमोल पाठ

मानव जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि यह नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और आत्मसम्मान पर आधारित एक गहरी यात्रा भी है। हम रोज़ाना रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि जो रोटी हम खा रहे हैं, वह वास्तव में हमारे अधिकार की है या नहीं। 'अधिकार की रोटी' का अर्थ केवल पेट भरने से नहीं, बल्कि उस रोटी के पीछे छिपी सच्चाई, परिश्रम और नैतिकता से है। इसी सत्य को एक साधारण-सी प्रतीत होने वाली कथा बड़े ही प्रभावशाली ढंग से समझाती है।

एक समय की बात है, एक राजा अपने दरबार में विद्वानों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहा था। चर्चा के दौरान 'अधिकार की रोटी' का विषय उठा। यह विषय सुनते ही राजा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि आखिर 'अधिकार की रोटी' क्या होती है। ब्राह्मण ने सीधे उत्तर देने के बजाय राजा से कहा कि उसके नगर में रहने वाली एक बूढ़ी महिला ही इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकती है। यह सुनकर राजा स्वयं उस महिला से मिलने के लिए निकल पड़ा।

राजा जब उस स्थान पर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर चरखे पर सूत कात रही थी। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और शांति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। राजा ने उसके पास जाकर विनम्रता से पूछा, "माई, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। कृपया बताइए कि 'अधिकार की रोटी' क्या होती है?"

बूढ़ी महिला ने राजा की ओर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, "बेटा, मेरे पास जो रोटी है, उसमें आधी मेरे अधिकार की है और आधी बिना अधिकार की।" यह उत्तर सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, "माई, यह आप क्या कह रही हैं? रोटी तो पूरी आपकी ही है, फिर आधी अधिकार की और आधी बिना अधिकार की कैसे हो सकती है?" बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, "मैं तुम्हें इसका कारण बताती हूं। एक दिन मैं इसी स्थान पर बैठकर सूत कात रही थी। धीरे-धीरे शाम हो गई और अंधेरा छा गया। मेरे पास दीपक जलाने के लिए तेल नहीं था। उसी समय यहां से एक जुलूस निकला, जिसमें मशालें जल रही थीं। मैंने सोचा कि जब तक यह जुलूस यहां से गुजर रहा है, तब तक मैं उसकी रोशनी का उपयोग कर लूं। मैंने अपना दीपक नहीं जलाया और उन्हीं मशालों की रोशनी में कुछ समय और सूत कातती रही। आधा सूत मैं पहले ही अपने परिश्रम से कात चुकी थी, लेकिन बाकी आधा मैंने दूसरों की रोशनी में काता। बाद में मैंने उस सूत को बेचकर आटा खरीदा और रोटी बनाई। इस प्रकार, जो सूत मैंने अपने बलबूते पर काता, उससे बनी रोटी मेरे अधिकार की है, लेकिन जो सूत मैंने दूसरों की रोशनी में काता, उस पर मेरा पूरा अधिकार नहीं है।"

बूढ़ी महिला की यह बात सुनकर राजा गहरे चिंतन में डूब गया। उसने महसूस किया कि अधिकार केवल उस पर होता है, जो पूरी तरह अपने परिश्रम और ईमानदारी से प्राप्त किया गया हो। यदि उसमें किसी भी प्रकार से दूसरों के संसाधनों या सहायता का अनुचित उपयोग हुआ है, तो वह पूरी तरह हमारा अधिकार नहीं रह जाता।

यह कहानी हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। आज के समय में जब लोग जल्दी सफलता पाने के लिए किसी भी साधन का उपयोग करने को तैयार हो जाते हैं, तब यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची सफलता वही है, जो ईमानदारी और परिश्रम से प्राप्त हो। किसी और की मेहनत, संसाधन या अधिकार का अनुचित लाभ उठाकर प्राप्त की गई चीज़ें भले ही बाहर से आकर्षक लगें, लेकिन वे हमें भीतर से संतोष नहीं दे सकतीं। अधिकार की रोटी का अर्थ केवल भोजन तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है—चाहे वह धन कमाना हो, पद प्राप्त करना हो या सम्मान हासिल करना हो। यदि हमने यह सब ईमानदारी और मेहनत से पाया है, तो वह हमारे अधिकार का है। लेकिन यदि उसमें किसी प्रकार की बेईमानी, छल या दूसरों के अधिकारों का हनन शामिल है, तो वह पूरी तरह हमारा नहीं है।

आज के आधुनिक युग में यह शिक्षा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तकनीक, संसाधनों और अवसरों की भरमार के बीच यह आवश्यक है कि हम यह समझें कि क्या हम इनका सही और नैतिक उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति दूसरों के काम का श्रेय लेता है, या किसी की मेहनत का फायदा उठाकर आगे बढ़ता है, तो वह भी 'बिना अधिकार की रोटी' ही खा रहा होता है। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह बूढ़ी महिला अत्यंत गरीब होने के बावजूद इतनी ईमानदार थी कि उसने अपने हिस्से की रोटी को भी पूरी तरह अपना नहीं माना। यह उसकी नैतिकता और आत्मसम्मान को दर्शाता है। आज के समय में जब लोग छोटी-छोटी बातों में भी समझौता कर लेते हैं, तब यह उदाहरण हमें सच्ची ईमानदारी का महत्व समझाता है।

अंततः, 'अधिकार की रोटी' केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि हमें केवल वही स्वीकार करना चाहिए, जो हमारे परिश्रम और ईमानदारी से प्राप्त हुआ हो। यही सच्चा संतोष और आत्मिक शांति का मार्ग है। यदि हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बेहतर होगा, बल्कि समाज में भी नैतिकता और विश्वास की नींव मजबूत होगी।

मानवता चुका रही संघर्षों-युद्धों की कीमत

समृद्ध देशों में स्थापित हथियार निर्माण उद्योग एक अत्यंत लाभकारी क्षेत्र बन चुका है। इन उद्योगों के कारण वैश्विक स्तर पर हथियारों की मांग बनी रहती है, और कई बार यह धारणा बनती है कि युद्ध और तनाव की स्थितियां इन उद्योगों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देती हैं। परिणामस्वरूप, हथियारों के निर्यात से संबंधित देशों की अर्थव्यवस्था और सरकारी राजस्व को भी लाभ होता है।

आज दुनिया में यह धारणा प्रबल होती है कि हथियार उद्योग के आर्थिक हित विश्व के विभिन्न हिस्सों में संघर्षों के बने रहने से जुड़े रहते हैं। एक ओर शक्तिशाली देश शांति और संवाद की आवश्यकता पर जोर देते हैं, वहीं दूसरी ओर कई बार उनके कदम ऐसे दिखाई देते हैं जो संघर्षों को लंबा खींच देते हैं। विशेष रूप से खनिज संसाधनों से समृद्ध छोटे देशों में होने वाले युद्ध अक्सर लंबी अवधि तक चलते हैं, जिनका सबसे अधिक बोझ आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। रूस द्वारा यूक्रेन के विरुद्ध शुरू किया गया युद्ध इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो खनिज संसाधनों और सामरिक हितों से जुड़ी जटिलताओं के कारण चार साल से जारी है।

वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के कार्यकाल में उसका अहम् सर्वोपरि है। ईरान के तेल के कुओं पर अधिकार करने की उसकी मंशा वही है जो वेनेजुएला की तेल धन पर कब्जा करने की थी। लेकिन इनका अधिनायकवाद चाहे बाहरी तौर पर इस्राइल के लोगों की रक्षा करने के रूप में उभरता है, लेकिन असल खलिश यही है कि ईरान ने अपने ही तरीके से जीने की हिम्मत क्यों की? यहां भी आठ-दस दिनों में युद्ध निपटा देने की कल्पना की गई थी। पहले ही दिन ईरान की सर्वोच्च सत्ता को साफ कर देने के बाद भी इस युद्ध का अंत अब तक नजर नहीं आता। अमेरिका को यह युद्ध नाको चने चबा गया है। वह खुद कह रहा है कि यह युद्ध लम्बा हो जाएगा, जिसका असंतोष अमेरिका के आम लोगों में भी अब नजर आने लगा है।

वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न हिस्सों—जैसे गाजा पट्टी, ईरान और अफगानिस्तान—में चल रहे संघर्ष यह दर्शाते हैं कि युद्धों का दायरा लगातार फैल रहा है। पारंपरिक रूप से युद्ध के कुछ मानवीय नियम माने जाते रहे हैं, जिनके अनुसार संघर्ष केवल सेनाओं तक सीमित होना चाहिए और आम नागरिकों, अस्पतालों तथा विद्यालयों को इससे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में यह देखा जा रहा है कि इन सिद्धांतों की अक्सर अनदेखी हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष नागरिक, मरीज और बच्चे भी युद्ध की विभीषिका का शिकार बन रहे हैं।

आधुनिक मारक हथियारों से लैस युद्धरत देश मानवीय मूल्यों की परवाह किए बगैर हिंसा के साथ मौत बरसा रहे हैं। इस्राइल और अमेरिका की साझी सेनाओं ने गाजा पट्टी को नष्ट कर दिया। हाल के संघर्षों में नागरिक क्षेत्रों पर हमलों को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। ईरान से जुड़े घटनाक्रमों में स्कूलों और आम नागरिकों पर हमलों के आरोप लगे, जिनमें अनेक मासूमों की मृत्यु की खबरें सामने आईं, हालांकि संबंधित पक्षों ने इन दावों से इनकार किया और केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही। इसी प्रकार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में भी नागरिक हानि की खबरें आई हैं, जिनमें अस्पतालों पर हमले और बड़ी संख्या में हताहत होने के दावे शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर, आधिकारिक स्तर पर इन दावों का खंडन किया गया है और सैन्य लक्ष्यों पर कार्रवाई की बात दोहराई गई है। इन घटनाओं ने एक बार फिर युद्ध के मानवीय नियमों और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदार पक्षों के विरुद्ध उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। भारत ने अफगानिस्तान के काबुल स्थित अस्पताल पर कथित हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे नागरिकों के विरुद्ध अमानवीय कृत्य और संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। संयुक्त राष्ट्र में भी इस प्रकार के हमलों पर चिंता जताई गई है।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि कई संघर्षों में नागरिकों, अस्पतालों और स्कूलों की सुरक्षा से जुड़े मानवीय सिद्धांतों की अनदेखी हो रही है। युद्ध व संघर्ष का सबसे अधिक दुष्प्रभाव आम लोगों पर पड़ रहा है। इसी बीच चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव भी वैश्विक चिंता का विषय हैं। कुल मिलाकर, यह स्थिति दर्शाती है कि युद्ध केवल रणनीतिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों और शांति के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। ऐसे समय में आवश्यक है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय सक्रिय भूमिका निभाए, संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता दे, तथा युद्धोन्माद को रोकने के लिए ठोस प्रयास करे, ताकि मानवता और वैश्विक शांति की रक्षा की जा सके।

अभियान

शत्रुंजय की सीढ़ियों पर आत्मा का आरोहण: पालीताणा की अनंत आस्था और कला की दिव्य गाथा

भारत की भूमि सदियों से आध्यात्मिकता, दर्शन और कला की अनूठी परंपराओं से समृद्ध रही है। इसी विरासत का एक अद्वितीय केंद्र है गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पालीताणा, जिसे 'मंदिरों का नगर' कहा जाता है। यह स्थान केवल भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना का ऐसा केंद्र है, जहां पहुंचकर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करता है। शत्रुंजय पर्वत की गोद में बसा यह नगर श्रद्धा, तपस्या और अहिंसा का जीवंत प्रतीक है, जो हर आगंतुक को आत्मिक ऊंचाइयों की ओर प्रेरित करता है।

पालीताणा का नाम सुनते ही आंखों के सामने सफेद संगमरमर से बने भव्य मंदिरों की एक श्रृंखला उभर आती है, जो पर्वत की ऊंचाइयों पर ऐसे सजी हैं मानो आकाश को छू रही हों। यह दृश्य केवल स्थापत्य कला का चमत्कार नहीं, बल्कि मानव की आस्था और समर्पण का प्रतीक भी है। यहां की हर सीढ़ी, हर पत्थर और हर मंदिर एक कहानी कहता है—एक ऐसी कहानी जो भक्ति, साधना और मोक्ष की राह से जुड़ी हुई है।

शत्रुंजय पर्वत, जो इस तीर्थ का हृदय है, जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि 24 तीर्थंकरों में से 23 ने इस पर्वत को अपनी उपस्थिति से पावन किया था। विशेष रूप से प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है, का इस स्थान से गहरा संबंध है। कहा जाता है कि उन्होंने यहां अनेक बार विचरण किया और अपने उपदेशों से इस भूमि को पवित्र किया। यही कारण है कि पालीताणा को 'शाश्वत तीर्थ' की संज्ञा दी जाती है, जहां अनगिनत आत्माओं ने मोक्ष की राह पाई।

पालीताणा की यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक साधना है। यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 3500 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह चढ़ाई केवल शारीरिक परिश्रम नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन का भी प्रतीक है। श्रद्धालु प्रातःकाल में यात्रा प्रारंभ करते हैं, अक्सर मौन रहकर और बिना भोजन के इस कठिन मार्ग को पार करते हैं। यह प्रक्रिया आत्मसंयम और समर्पण का प्रतीक बन जाती है, जिसमें हर कदम व्यक्ति को अपने भीतर की शुद्धता के और करीब ले जाता है।

पर्वत की चोटी पर पहुंचने पर जो दृश्य सामने आता है, वह किसी स्वप्न से कम नहीं होता। लगभग 900 मंदिरों का समूह, जिनमें 17,000 से अधिक प्रतिमाएं स्थापित हैं, एक दिव्य संसार की अनुभूति कराता है। इन मंदिरों की नक्काशी इतनी सूक्ष्म और अद्भुत है कि हर एक आकृति में शिल्पकारों की कुशलता और श्रद्धा झलकती है। संगमरमर पर उकेरी गई ये कलाकृतियां केवल सजावट नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास हैं, जो सदियों पुरानी परंपराओं और विश्वासों को संजोए हुए हैं।

इन मंदिरों में आदिश्वर मंदिर का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। यह पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और इसे इस तीर्थ का केंद्र माना जाता है। भगवान आदिनाथ की स्वर्णमयी प्रतिमा यहां स्थापित है, जो भक्तों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है। मंदिर की भव्यता और उसकी शांति मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जहां व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के बेहद करीब महसूस करता है।

पालीताणा में चौमुख मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसकी संरचना चार दिशाओं में खुली हुई है। यह मंदिर इस विचार का प्रतीक है कि ईश्वर हर दिशा में उपस्थित हैं और उनकी भक्ति किसी एक दिशा या सीमाओं में बंधी नहीं है। यहां खड़े होकर जब श्रद्धालु चारों ओर देखते हैं, तो उन्हें हर दिशा में एक ही दिव्यता का अनुभव होता है।

शत्रुंजय पर्वत पर स्थित मंदिरों को विभिन्न समूहों में बांटा गया है, जिन्हें 'टूंक' कहा जाता है। प्रत्येक टूंक का अपना अलग महत्व और इतिहास है। कुमारपाल टूंक, विमलशाह टूंक और अन्य समूह इस स्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गहराई को दर्शाते हैं। इन टूंकों में स्थित मंदिरों की संरचना और नक्काशी यह प्रमाणित करती है कि उस समय के शिल्पकार न केवल तकनीकी रूप से दक्ष थे, बल्कि वे अपनी कला में आध्यात्मिकता को भी समाहित करते थे।

पालीताणा का महत्व केवल इसके मंदिरों तक सीमित नहीं है। यहां के अन्य पवित्र स्थल भी इसकी आध्यात्मिकता को और समृद्ध बनाते हैं। पुंडरीक स्वामी का मंदिर, अष्टपद मंदिर, रायण वृक्ष और भरत चक्रवर्ती से जुड़े स्थान इस पर्वत की पवित्रता को और भी गहरा बनाते हैं। विशेष रूप से रायण वृक्ष के नीचे की गई भगवान आदिनाथ की तपस्या की कथा श्रद्धालुओं के मन में गहरी श्रद्धा उत्पन्न करती है।

पालीताणा की एक और विशेषता है इसके कठोर नियम, जो इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखते हैं। यहां सूर्यास्त के बाद किसी भी व्यक्ति को पर्वत पर रुकने की अनुमति नहीं है। यह मान्यता है कि रात के समय यहां देवताओं का वास होता है। यह नियम केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता के नियमों का पालन आवश्यक होता है।

पालीताणा को विश्व का पहला कानूनी रूप से शाकाहारी शहर होने का गौरव भी प्राप्त है। वर्ष 2014 में यहां मांसाहार, अंडे और पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। यह निर्णय जैन धर्म के मूल सिद्धांत "अहिंसा परमो धर्मः" का सजीव उदाहरण है। यह केवल एक नियम नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जो यह सिखाता है कि सभी जीवों के प्रति करुणा और दया ही सच्ची मानवता है।

आज के आधुनिक युग में, जहां जीवन की गति तेज हो गई है और लोग भौतिक उपलब्धियों के पीछे भाग रहे हैं, पालीताणा जैसे स्थान हमें ठहरकर सोचने का अवसर देते हैं। यह हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मिक संतुलन भी है। यहां का शांत वातावरण, मंदिरों की दिव्यता और पर्वत की ऊंचाई हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है।

पालीताणा केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक अनुभव है—एक ऐसा अनुभव जो मन, बुद्धि और आत्मा को एक साथ स्पर्श करता है। यहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर लौटता है—कोई शांति, कोई प्रेरणा, तो कोई आत्मज्ञान। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में सादगी, अहिंसा और भक्ति को अपनाएं, तो हम भी अपने भीतर उसी दिव्यता को महसूस कर सकते हैं, जो इस पवित्र भूमि की हर शिला में बसती है।

इस प्रकार पालीताणा केवल मंदिरों का नगर नहीं, बल्कि वह पवित्र धरा है जहां मानव और परमात्मा के बीच की दूरी कम हो जाती है। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि सच्ची यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है, और वही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

तेज हवाएं, बारिश और बर्फबारी से बदला देश का मौसम, दिल्ली में येलो अलर्ट से लेकर पहाड़ों पर भारी असर, 15 राज्यों में अलर्ट

नई दिल्ली। पूरे देश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तथा मध्य और पश्चिम भारत तक बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी Delhi में जहां आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो चुका है, वहीं मौसम विभाग ने 30 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अनुमान है कि बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना तो होगा, लेकिन अस्थिर भी बना रहेगा। राजधानी में न्यूनतम तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि 31 मार्च को भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। इतना ही नहीं, अप्रैल के पहले सप्ताह में भी यह सिलसिला जारी रह सकता है और 3 तथा 4 अप्रैल को फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

इस पूरे मौसम परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ को माना जा रहा है, जिसने उत्तर भारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके प्रभाव से Jammu and Kashmir, Ladakh और Himachal Pradesh के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश दर्ज की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल-स्पीति जैसे क्षेत्रों में

बर्फ गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। खासतौर पर Atal Tunnel और मनाली के आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण यातायात पर असर पड़ा है और प्रशासन को सुरक्षा के मद्देनजर सोलांग बैरियर से आगे छोटे वाहनों और दोपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी है।

शिमला स्थित मौसम विभाग ने मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। राज्य में 4 अप्रैल तक मौसम के खराब बने रहने का अनुमान है, जिससे पर्यटन और स्थानीय गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है।

उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जहां 30 और 31 मार्च को हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 31 मार्च को कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश का अनुमान है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है, जिससे खासतौर पर किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।

पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram और Tripura में 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। इससे न केवल जनजीवन प्रभावित हो सकता है, बल्कि भूस्खलन और जलभराव जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।

पूर्वी भारत के राज्यों में भी यही स्थिति बनी हुई है। West Bengal, Bihar, Jharkhand और Odisha में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा। 31 मार्च को कुछ इलाकों में हवाओं की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो सामान्य जीवन को प्रभावित कर सकती है और पेड़ गिरने या बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। मध्य और पश्चिम भारत भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। Madhya Pradesh और Chhattisgarh में 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं Maharashtra और Gujarat में भी गरज-चमक के साथ बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का व्यापक मौसम परिवर्तन इस समय असामान्य नहीं है, लेकिन इसकी तीव्रता और एक साथ कई क्षेत्रों में प्रभाव जरूर चिंता का विषय है। किसानों के लिए यह समय खास तौर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि फसल कटाई के दौरान बारिश और ओलावृष्टि नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में तेज हवाएं और बारिश यातायात, बिजली आपूर्ति और दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती हैं।

फिलहाल, मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। आने वाले कुछ दिन मौसम के लिहाज से काफी संवेदनशील रहने वाले हैं, जहां प्रकृति का यह बदला हुआ रूप देश के बड़े हिस्से को प्रभावित करता रहेगा।

हाई रिटर्न के जाल में फंसे निवेशक, राजकोट में 1.74 करोड़ की ठगी का खुलासा, परिवार पर गंभीर आरोप

Rajkot। तेज मुनाफे के लालच में निवेश करने वालों के लिए एक बार फिर बड़ा चेतावनी भरा मामला सामने आया है, जहां कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से लोगों को अधिक रिटर्न का भरोसा दिलाकर करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दिया गया। इस पूरे प्रकरण ने न केवल निवेशकों की आर्थिक सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि कैसे भरोसे और संबंधों का इस्तेमाल कर लोगों को वित्तीय जाल में फंसाया जाता है। मामले में अरविंद लालजी खूंट, उनकी पत्नी ज्योत्सनाबेन और बेटे सागर के खिलाफ अपराध शाखा में शिकायत दर्ज की गई है, जबकि जांच की जिम्मेदारी आर्थिक अपराध निवारण शाखा (EOW) को सौंपी गई है। शुरुआती जांच में ही यह सामने आया है कि ठगी की कुल राशि करीब 1.74 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है।

पूरे घटनाक्रम की शुरुआत एक भरोसेमंद परिचय से हुई, जो धीरे-धीरे एक बड़े निवेश जाल में बदल गया। मवडी क्षेत्र के चंद्रेशनगर निवासी वीरेंद्रसिंह परमार

ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी मुलाकात आरोपी सागर से लगभग दस वर्ष पहले हुई थी। समय के साथ यह परिचय विश्वास में बदल गया और इसी विश्वास का फायदा उठाते हुए वर्ष 2023 में सागर ने उन्हें दुबई स्थित "मिशा इन्वेस्टमेंट" नामक एक ट्रेडिंग कंपनी में निवेश का प्रस्ताव दिया। निवेश पर हर महीने 4 से 5 प्रतिशत तक रिटर्न देने का दावा किया गया, जो सामान्य बाजार दरों की तुलना में काफी अधिक था और इसी लालच ने निवेशकों को आकर्षित किया।

शिकायत के अनुसार, शुरुआत में आरोपियों ने अपनी योजना को विश्वसनीय बनाने के लिए निवेशकों को नियमित रूप से रिटर्न देना शुरू किया। वीरेंद्रसिंह ने पहले 9 लाख रुपये का निवेश किया, जिस पर उन्हें 45 हजार रुपये का रिटर्न मिला। इस शुरुआती लाभ ने उनका भरोसा मजबूत कर दिया। इसके बाद उनके छोटे भाई युवराज सिंह ने भी 5.47 लाख रुपये निवेश किए। मार्च 2025 तक दोनों को नियमित रिटर्न मिलता रहा, जिससे यह योजना पूरी तरह सुरक्षित और लाभदायक प्रतीत होने लगी। धीरे-धीरे यह निवेश केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रिश्तेदारों और मित्रों तक फैल गया। वीरेंद्रसिंह ने खुद कुल 19.43 लाख रुपये का निवेश किया और अपने जान-पहचान के लोगों से भी करीब 39 लाख रुपये निवेश करवाए। इस तरह कुल 56.43 लाख रुपये इस योजना में लगाए गए। हालांकि, इस पूरी राशि में से केवल 11.53 लाख रुपये ही रिटर्न के रूप में मिले, जबकि 44.90 लाख रुपये अब तक वापस नहीं किए गए हैं। यही नहीं, अन्य निवेशकों के साथ भी इसी तरह का पैटर्न अपनाया गया, जहां शुरुआत में छोटे-छोटे रिटर्न देकर भरोसा जीता गया और बाद में बड़ी रकम फंसाई गई। अन्य पीड़ितों में धार्मिक दिलीपभाई आह्या ने अपने और अपने परिजनों के नाम पर करीब 50 लाख रुपये निवेश किए, जिसमें से उन्हें केवल 5.88 लाख रुपये ही वापस मिले, जबकि 44.12 लाख रुपये अब भी बकाया हैं। इसी तरह धर्मिल जगदीशभाई पांभर ने 18.50 लाख रुपये निवेश किए, जिसमें से मात्र 1.84 लाख रुपये रिटर्न मिला और 16.65 लाख रुपये फंसे हुए हैं। एक अन्य निवेशक हरेशभाई मेनपरा ने 55 लाख रुपये लगाए, जिनमें से केवल 7.52 लाख रुपये ही लौटाए गए, जबकि 42.48 लाख रुपये अब तक वापस नहीं किए गए हैं।

इन सभी मामलों को जोड़कर देखा जाए तो आरोपियों ने कुल 1.74 करोड़ रुपये निवेश के नाम पर एकत्र किए, जिसमें से लगभग 26.77 लाख रुपये ही रिटर्न के रूप में दिए गए। शेष राशि निवेशकों को नहीं लौटाई गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई सामान्य निवेश असफलता नहीं, बल्कि सुनियोजित वित्तीय धोखाधड़ी का मामला हो सकता है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की भूमिका की गहराई से पड़ताल की जा रही है। आर्थिक अपराध निवारण शाखा इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस योजना के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या संगठित गिरोह काम कर रहा था। साथ ही, यह भी देखा जा रहा है कि कथित "मिशा इन्वेस्टमेंट" कंपनी वास्तव में अस्तित्व में है या केवल एक नाम के तौर पर इस्तेमाल की गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में सबसे बड़ा हथियार 'विश्वास' होता है, जिसे धीरे-धीरे बनाया जाता है और फिर उसी के आधार पर लोगों को बड़े निवेश के लिए प्रेरित किया जाता है। उच्च रिटर्न का लालच, शुरुआती भुगतान और परिचित व्यक्ति की सिफारिश—ये सभी तत्व मिलकर एक ऐसा जाल तैयार करते हैं, जिसमें फंसना आसान होता है, लेकिन निकलना बेहद कठिन।

यह मामला एक बार फिर यह चेतावनी देता है कि किसी भी निवेश से पहले उसकी पूरी जांच-पड़ताल करना बेहद जरूरी है। खासकर जब रिटर्न असामान्य रूप से अधिक हो, तो सतर्क रहना और भी आवश्यक हो जाता है। फिलहाल, सभी पीड़ितों की नजर अब जांच एजेंसियों पर टिकी है, जो इस पूरे प्रकरण का सच सामने लाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटी हैं।

बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल: नितिन नवीन और नीतीश कुमार के इस्तीफों से नई सियासी दिशा

Patna। बिहार की राजनीति में एक साथ हुए दो महत्वपूर्ण इस्तीफों ने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। एक ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता Nitin Nabin ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने विधान परिषद से इस्तीफा देकर केंद्र की राजनीति की ओर कदम बढ़ाया है। इन दोनों फैसलों को राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और नई जिम्मेदारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

सबसे पहले बात करें नितिन नवीन के इस्तीफे की, तो वह पटना के प्रमुख क्षेत्र Bankipur Assembly Constituency से विधायक थे और लंबे समय से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करते हुए अपने राजनीतिक सफर को याद किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में उपचुनाव के जरिए पहली बार विधानसभा पहुंचने के बाद उन्हें लगातार जनता की सेवा करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, विकास कार्यों और जनसमस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी।

नितिन नवीन ने अपने संदेश में यह भी कहा कि बांकीपुर की जनता ने उन्हें बार-बार अपना प्रतिनिधि चुनकर जो विश्वास जताया, वह उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी रहा। उन्होंने विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों ही मंचों पर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। उनके इस्तीफे को पार्टी में मिली नई जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर नई भूमिका को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विधायक पद छोड़ने के बावजूद उनका जनसेवा का संकल्प कमजोर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी में भी वे बिहार और विशेष रूप से अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। साथ ही, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ उनका जुड़ाव पहले की तरह बना रहेगा।

दूसरी ओर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की है। उनका यह कदम राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उठाया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार, कोई भी जनप्रतिनिधि एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता, इसलिए राज्यसभा सदस्य बनने के बाद विधान परिषद की सदस्यता छोड़ना अनिवार्य हो जाता है।

आरबीआई की 'कैश स्ट्रैटेजी' से बैंकिंग सिस्टम को राहत, 84,582 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी से बढ़ेगा कर्ज प्रवाह

Reserve Bank of India ने एक बार फिर सक्रिय भूमिका निभाते हुए बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने लगातार दो दिनों में वेरिएबल रेट रेपो (VRR) नीलामियों के जरिए कुल 84,582 करोड़ रुपये की अस्थायी लिक्विडिटी सिस्टम में डाली है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बैंकिंग सेक्टर में अल्पकालिक नकदी दबाव देखने को मिल रहा था और वित्तीय संस्थानों को तत्काल फंडिंग की आवश्यकता महसूस हो रही थी।

दरअसल, जब बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी होती है, तो इसका सीधा असर कर्ज वितरण और ब्याज दरों पर पड़ता है। इसी को संतुलित करने के लिए आरबीआई समय-समय पर VRR जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता है। इस बार भी केंद्रीय बैंक ने दो चरणों में यह प्रक्रिया पूरी की। पहले चरण में तीन-दिवसीय वीआरआर नीलामी के जरिए 50,001 करोड़ रुपये सिस्टम में डाले गए। इस नीलामी में बैंकों की ओर से अपेक्षा से अधिक बोलियां आईं, जिससे यह संकेत मिला कि बाजार में नकदी की मांग काफी मजबूत है। इस चरण में कट-ऑफ दर 5.34 प्रतिशत और औसत भारित दर 5.44 प्रतिशत रही, जो यह दर्शाती है कि बैंक थोड़ी ऊंची दर पर भी फंड लेने को तैयार थे।

इसके बाद दूसरे चरण में 34,581 करोड़

रुपये की अतिरिक्त लिक्विडिटी उपलब्ध कराई गई। इस बार कट-ऑफ दर 5.26 प्रतिशत और औसत दर 5.30 प्रतिशत रही। हालांकि इस नीलामी में बोलियां अपेक्षाकृत कम रहीं, लेकिन यह संकेत देती हैं कि पहले चरण में ही बैंकों की तत्काल जरूरत का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका था। कुल मिलाकर, इन दोनों नीलामियों के जरिए 84,582 करोड़ रुपये की राशि सिस्टम में प्रवाहित की गई, जिससे बैंकिंग सेक्टर को तात्कालिक राहत मिली है।

अगर व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मार्च के अंतिम सप्ताह तक बैंकिंग प्रणाली में कुल तरलता लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष में रहने का अनुमान है। यह स्थिति दर्शाती है कि आरबीआई केवल तात्कालिक संकट को संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे सिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हाल के दिनों में केंद्रीय बैंक ने विभिन्न अवधियों के वीआरआर ऑपरेशनों के माध्यम से 2.73 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अस्थायी लिक्विडिटी पहले ही सिस्टम में डाल दी है।

इसके साथ ही, आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) के जरिए भी स्थायी आधार पर नकदी उपलब्ध कराई है। OMO के तहत केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करता है, जिससे बाजार में स्थायी रूप से धन का प्रवाह बढ़ता है। इस दोहरी रणनीति—अस्थायी (VRR) और स्थायी (OMO)—के जरिए आरबीआई यह सुनिश्चित कर रहा है कि बैंकिंग प्रणाली में न तो नकदी की कमी हो और न ही अत्यधिक अधिशेष की स्थिति बने, जिससे महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम का सीधा फायदा आम अर्थव्यवस्था को मिलेगा। जब बैंकों के पास पर्याप्त नकदी होती है, तो वे आसानी से उद्योगों, व्यापारियों और आम लोगों को कर्ज दे सकते हैं। इससे निवेश और उपभोग दोनों में वृद्धि होती है, जो आर्थिक विकास को गति देती है। साथ ही, पर्याप्त लिक्विडिटी होने से ब्याज दरों पर भी नियंत्रण बना रहता है, जिससे उधारी सस्ती बनी रहती है।

हालांकि, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आरबीआई इन उपायों को बहुत संतुलित तरीके से लागू करता है। अत्यधिक नकदी प्रवाह से महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए केंद्रीय बैंक लगातार बाजार की स्थितियों पर नजर रखता है और जरूरत के अनुसार अपने कदमों में बदलाव करता है। कुल मिलाकर, 84,582 करोड़ रुपये की यह लिक्विडिटी इंजेक्शन केवल एक तात्कालिक राहत नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना, कर्ज प्रवाह को बनाए रखना और व्यापक अर्थव्यवस्था को स्थिर गति देना है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि आरबीआई अपने अन्य मौद्रिक उपकरणों के साथ इस संतुलन को किस तरह बनाए रखता है।

स्पेशलिटी मेडिसिन्स की सपाट लिस्टिंग, हल्की तेजी से निवेशकों को मामूली मुनाफा

नई दिल्ली। फार्मा सेक्टर की कंपनी Speciality Medicines Limited ने शेयर बाजार में एंट्री तो बिना किसी शोर-शराबे के की, लेकिन दिनभर के कारोबार में जो हलचल देखने को मिली, उसने यह जरूर संकेत दिया कि निवेशकों की नजर इस कंपनी पर बनी हुई है। लिस्टिंग के दिन शेयर का प्रदर्शन न तो बहुत उत्साहजनक रहा और न ही निराशाजनक, बल्कि यह एक संतुलित और परिपक्व बाजार प्रतिक्रिया का उदाहरण बनकर सामने आया।

कंपनी का शेयर BSE SME Platform पर 124 रुपये के इश्यू प्राइस पर ही सूचीबद्ध हुआ। आमतौर पर निवेशक आईपीओ से लिस्टिंग गेन की उम्मीद रखते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। यह इस बात का संकेत है कि इश्यू प्राइस पहले से ही बाजार के हिसाब से संतुलित रखा गया था। हालांकि, लिस्टिंग के तुरंत बाद बाजार में हल्की खरीदारी देखने को मिली, जिससे शेयर की कीमत बढ़कर लगभग 129.50 रुपये तक पहुंच गई। इस स्तर पर जिन निवेशकों ने समय पर मुनाफा बुक किया, उन्हें अच्छा इंट्राडे लाभ मिला।

लेकिन बाजार की प्रकृति के अनुसार, जहां तेजी आती है, वहां मुनाफावसूली भी देखने को मिलती है। यही इस शेयर के साथ भी हुआ। ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद कुछ निवेशकों ने मुनाफा बुक करना शुरू किया, जिससे कीमत में थोड़ी नरमी आई और अंततः शेयर 125.80 रुपये पर बंद हुआ। इस तरह पहले दिन कुल मिलाकर निवेशकों को लगभग 1.45 प्रतिशत का मामूली लाभ मिला, जो यह दर्शाता है कि बाजार ने कंपनी को लेकर अभी 'वेट एंड वॉच' की रणनीति अपनाई हुई है।

अगर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो यह इश्यू लगभग 2.27 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसे औसत प्रतिक्रिया माना जाता है। दिलचस्प पहलू यह रहा कि इस इश्यू में संस्थागत निवेशकों (QIB) ने अपेक्षाकृत अधिक दिलचस्पी दिखाई, जबकि खुदरा निवेशकों की भागीदारी सीमित रही। यह प्रवृत्ति अक्सर तब देखने को मिलती है जब बड़े निवेशक कंपनी के फंडामेंटल्स और ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर आश्वस्त होते हैं, लेकिन आम निवेशक थोड़ी सतर्कता बरतते हैं।

कंपनी ने आईपीओ के जरिए जुटाई गई करीब 29 करोड़ रुपये की राशि को अपने विस्तार और विकास योजनाओं में लगाने की योजना बनाई है। इसमें अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर निवेश, नए उत्पादों की लॉन्चिंग, मार्केटिंग नेटवर्क को मजबूत करना और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करना शामिल है। फार्मा इंडस्ट्री में R&D का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि यही किसी कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को तय करता है। ऐसे में इस दिशा में किया गया निवेश कंपनी के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है।

वित्तीय स्थिति की बात करें तो कंपनी ने हाल के वर्षों में स्थिर सुधार दिखाया है। राजस्व में वृद्धि और मुनाफे में बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि कंपनी अपने व्यवसाय को विस्तार देने में सफल रही है। साथ ही, EBITDA और नेटवर्थ में सुधार कंपनी की ऑपरेशनल मजबूती को दर्शाता है। हालांकि, कर्ज में बढ़ोतरी एक ऐसा पहलू है जिस पर निवेशकों को नजर बनाए रखने की जरूरत होगी, क्योंकि अत्यधिक ऋण भविष्य में जोखिम पैदा कर सकता है।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की सपाट लिस्टिंग उन कंपनियों के लिए सामान्य मानी जाती है, जिनका मूल्यांकन पहले से ही यथार्थवादी होता है। ऐसे मामलों में शेयरों में अचानक बड़ी तेजी या गिरावट की संभावना कम रहती है और वे धीरे-धीरे अपने प्रदर्शन के आधार पर निवेशकों का भरोसा जीतते हैं। पहले दिन की सीमित बढ़त यह संकेत देती है कि बाजार में कंपनी को लेकर पूरी तरह से नकारात्मक धारणा नहीं है, बल्कि निवेशक इसके आगामी नतीजों और ग्रोथ पर नजर रख रहे हैं।

एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि SME प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध कंपनियों में अक्सर वोलैटिलिटी अधिक देखने को मिलती है, लेकिन इस शेयर ने अपेक्षाकृत स्थिर प्रदर्शन दिखाया। यह निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत हो सकता है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि शेयर में अत्यधिक सट्टा गतिविधि नहीं हो रही है और कीमतें वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर तय हो रही हैं।

कुल मिलाकर, स्पेशलिटी मेडिसिन्स लिमिटेड की लिस्टिंग एक संतुलित शुरुआत के रूप में देखी जा सकती है। यह न तो तेज मुनाफे की कहानी है और न ही किसी बड़ी गिरावट की, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां कंपनी को खुद को साबित करने का समय दिया जा रहा है। आने वाले समय में कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन, नए उत्पादों की सफलता और फार्मा सेक्टर की समग्र स्थिति यह तय करेगी कि यह शेयर निवेशकों के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। फिलहाल, यह एक ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर बनाए रखना समझदारी भरा कदम माना जा सकता है।

बारनवापारा में लौटे काले हिरण, पुनर्स्थापन से फिर जगेगी घासभूमि की धड़कन

Raipur। छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन्य क्षेत्र Barnawapara Wildlife Sanctuary में काले हिरणों (ब्लैकबक) की वापसी ने संरक्षण प्रयासों को नई ऊर्जा दी है। वन विभाग ने वैज्ञानिक पद्धति अपनाते हुए कुल 34 काले हिरणों को दो चरणों में उनके प्राकृतिक आवास में सफलतापूर्वक छोड़ा है। यह पहल केवल संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं, बल्कि एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम है, जो कभी इस क्षेत्र की पहचान हुआ करता था।

यह पूरा पुनर्स्थापन अभियान अभयारण्य के भीतर स्थापित ब्लैकबक संरक्षण केंद्र से शुरू हुआ, जहां इन हिरणों को नियंत्रित वातावरण में पाला और तैयार किया गया था। इसके बाद सावधानीपूर्वक इन्हें प्राकृतिक घासभूमि क्षेत्र—रामपुर ग्रासलैंड—में छोड़ा गया। यहां पहले से मौजूद ब्लैकबक समूह के साथ इनका जुड़ना इस बात का संकेत है कि यह पुनर्स्थापन केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से सफल हो रहा है। वन अधिकारियों के अनुसार, इस वर्ष कुल 60 ब्लैकबक को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें यह पहला बड़ा चरण माना जा रहा है।

इस पूरी प्रक्रिया में वैज्ञानिक मानकों का विशेष ध्यान रखा गया। स्थानांतरण के दौरान हिरणों को न्यूनतम तनाव हो, इसके लिए विशेष ट्रांसपोर्ट केज, नियंत्रित मूवमेंट और चरणबद्ध रिलीज तकनीक अपनाई गई। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी वन्यजीव के पुनर्स्थापन में सबसे बड़ी चुनौती उसका नए वातावरण में अनुकूलन होता है। ऐसे में शुरुआती दिनों की निगरानी बेहद अहम होती है। इसी कारण वन विभाग द्वारा इन सभी हिरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, जिसमें उनकी गतिविधियों, भोजन, समूह व्यवहार और सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जाएगी। काले हिरण भारत के घासभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण शाकाहारी जीवों में से एक हैं। Blackbuck अपनी तेज रफ्तार और विशिष्ट सर्पिल सींगों के लिए जाना जाता है। नर का रंग गहरा भूरा या लगभग

काला होता है, जबकि मादा हल्के भूरे रंग की होती है। ये खुले मैदानों और घास के विस्तृत क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, जहां वे समूह में विचरण करते हैं। इनके मौजूद रहने से घासभूमि का संतुलन बना रहता है, क्योंकि ये वनस्पति को नियंत्रित करते हैं और अन्य जीवों के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां तैयार करते हैं।

भारत में ब्लैकबक को Wildlife Protection Act 1972 के तहत संरक्षित प्रजाति का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में देश में इनकी संख्या लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच आंकी जाती है, जो पिछले कुछ दशकों में संरक्षण प्रयासों के कारण बढ़ी है। गुजरात के वेलावदर क्षेत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इनकी अच्छी उपस्थिति दर्ज की गई है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्र में भी ब्लैकबक देखे जाते हैं, जो इनके व्यापक वितरण को दर्शाता है। बारनवापारा अभयारण्य स्वयं में जैव विविधता का एक समृद्ध केंद्र है। यहां 30 से अधिक स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें चितल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर और भालू शामिल हैं। इसके अलावा 150 से अधिक पक्षी प्रजातियां और कई सरीसृप व उभयचर जीव इस क्षेत्र को एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ऐसे में ब्लैकबक की वापसी इस संतुलन को और मजबूत करेगी, क्योंकि यह प्रजाति घासभूमि के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है।

इतिहास पर नजर डालें तो एक समय ऐसा भी था जब छत्तीसगढ़ के घासभूमि क्षेत्रों में ब्लैकबक आमतौर पर देखे जाते थे। लेकिन अवैध शिकार, बढ़ता मानव हस्तक्षेप और आवास की कमी ने इन्हें धीरे-धीरे इस क्षेत्र से लगभग खत्म कर दिया। यही कारण है कि वर्तमान पुनर्स्थापन अभियान को केवल संरक्षण नहीं, बल्कि 'पुनर्जीवन' की प्रक्रिया माना जा रहा है। यह प्रयास दिखाता है कि यदि योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, तो विलुप्तप्राय स्थिति तक पहुंच चुकी प्रजातियों को भी वापस लाया जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल का असर केवल वन्यजीवों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा। घासभूमि के पुनर्जीवित होने से अन्य शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के लिए भी बेहतर परिस्थितियां बनेंगी। साथ ही, यह स्थानीय समुदायों के लिए भी सकारात्मक संकेत है, क्योंकि स्वस्थ वन्यजीव क्षेत्र पर्यटन और आजीविका के अवसर भी बढ़ाते हैं।

कुल मिलाकर, बारनवापारा में काले हिरणों का यह पुनर्स्थापन अभियान संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह केवल आंकड़ों की उपलब्धि नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच संतुलन स्थापित करने की एक सार्थक पहल है। आने वाले समय में यदि यह प्रयास इसी तरह जारी रहता है, तो वह दिन दूर नहीं जब बारनवापारा की घासभूमियां फिर से काले हिरणों की दौड़ से जीवंत हो उठेंगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 31 मार्च को गुजरात की यात्रा पर, वाव-थराद में 19,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे

- भारत सरकार के ऊर्जा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा रेलवे मंत्रालय के 10,900 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा
- गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग अंतर्गत 5,200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया जाएगा
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रधानमंत्री गुजरात के 34 जिलों में 38,949 आवासों में नागरिकों का गृह प्रवेश कराएंगे

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आगामी 31 मार्च, 2026 को गुजरात की यात्रा पर आएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वाव-थराद से भारत सरकार तथा गुजरात सरकार के कुल मिलाकर 19,806.9 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें भारत सरकार के ऊर्जा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा रेलवे मंत्रालयों के 10,921 करोड़ रुपए के तथा गुजरात सरकार के शहरी विकास, जल संसाधन, जलापूर्ति, सड़क एवं भवन, जीआईडीसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यटन तथा आदिजाति विकास विभागों के 8,886 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास शामिल है। वाव-थराद में आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी सहित भारत एवं गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत गुजरात में 10,921 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण तथा शिलान्यास

उल्लेखनीय है कि कच्छ जिले के खावडा में विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी (आरई) पार्क निर्माणाधीन है। आगामी 31 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी खावडा के आरई पार्क के लिए ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत 3,645 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स द्वारा हजारों मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का राष्ट्रीय ग्रिड के साथ प्रभावी जुड़ाव सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके कारण हरित ऊर्जा की व्यापकता तथा ऊर्जा सुरक्षा मजबूत बनेगी।

इसके अलावा; भारत सरकार के सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अंतर्गत इडर-बारडोली बाईपास फोर लेन रोड (705 करोड़ रुपए की लागत से) और धोळावीरा-मौवाणा-वोवा-सांतलपुर सेक्शन (575 करोड़ रुपए की लागत से) शिलान्यास तथा अहमदाबाद-धोलेरा पैकेज 1 (1,298 करोड़ रुपए की लागत से), पैकेज 2 (1,415 करोड़ रुपए की लागत से, पैकेज 3 (1,034 करोड़ रुपए की लागत से और पैकेज 4 (1,358 करोड़ रुपए की लागत से) का लोकार्पण किया जाएगा। भारत सरकार के रेल मंत्रालय के 891 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया जाएगा। इनमें हिंमतनगर-खेडब्रह्मा ब्रॉडगेज लाइन, गांधीधाम-आदिपुर के बीच क्वाड्रपलिंग तथा राजकोट-कालानुस डबलिंग प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में कालानुस-जामनगर डबलिंग जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसी प्रकार; खेडब्रह्मा-हिंतमनगर-असारवा ट्रेन को खेडब्रह्मा से हरी झंडी दिखाई जाएगी। कुल मिलाकर भारत सरकार के इन तीन मंत्रालयों के 10,921 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा।

गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग अंतर्गत सर्वाधिक 5,295.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास

आगामी 31 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत 8,886 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इनमें शहरी विकास विभागांतर्गत सर्वाधिक 5,295.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण-शिलान्यास किया जाने वाला है। इन प्रोजेक्ट्स में मुख्य रूप से अहमदाबाद एवं गांधीनगर के विकास कार्य शामिल हैं; जिनमें अहमदाबाद में खारीकट कैनाल विकास, अहमदाबाद महानगर पालिका की बीआरटीएस व एएमटीएस बस सर्विस का मॉडर्नाइजेशन, वर्तमान सुभाषब्रिज को तोड़कर नए फोर लेन ब्रिज का कन्स्ट्रक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवासीय घरों का निर्माण, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम आदि जैसे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण-शिलान्यास शामिल हैं।

गांधीनगर में ईडब्ल्यूएस के लिए आवासीयों घरों का निर्माण, गांधीनगर महानगर पालिका के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से अडालज टीएसपीएस तक खुले खुदाई कार्य (लंबाई : 2420 मीटर) और माइक्रोटनलिंग (लंबाई : 3180 मीटर) द्वारा 1800 मिमीलीटर गटर ट्रंक डालने, पेथापुर में 15 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, रांधेजा में 4 तालाबों की इंटरलिंकिंग तथा स्टॉर्म वॉटर लाइन बिछाने का कार्य आदि प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण-शिलान्यास किया जाएगा।

शहरी विकास विभाग के अलावा; गुजरात सरकार के जल संसाधन, जलापूर्ति, सड़क एवं भवन, जीआईडीसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यटन, आदिजाति तथा ग्रामीण विकास विभागों के भी विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। इतना ही नहीं; प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत गुजरात के 34 जिलों के 38,949 आवासों में नागरिकों का गृह प्रवेश कराएंगे, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए अपने घर का सपना साकार होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की वर्चुअल उपस्थिति में तापी जिले को मिली 1600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की भेंट

- तापी के उच्छल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने तापी के 136 गाँवों के लिए 962 करोड़ रुपए की उद्वहन सिंचाई योजना का ई-लोकार्पण किया, 28 हजार हेक्टेयर भूमि को होगा लाभ
- 651 करोड़ रुपए की बोरीसावर योजना के ई-शिलान्यास से सोनगढ-व्यारा के 29 गाँवों की 8 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचाई की सुविधा से लाभान्वित होगी
- केबिनेट मंत्री श्री नरेशभाई पटेल, राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल तथा राज्य मंत्री डॉ. जयरामभाई गामित उपस्थित रहे

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गांधीनगर से वर्चुअल माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों तथा तापी जिले के विकास के लिए अनुमानित 1600 करोड़ रुपए की उकाई जलाशय आधारित सोनगढ, उच्छल, नीझर उद्वहन सिंचाई योजना तथा बोरीसावर योजना का ई-लोकार्पण व ई-शिलान्यास किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा सेचुरेशन एप्रोच पर बल दिया है। प्रधानमंत्री के गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान वनबंधु कल्याण योजना के जरिये आदिजाति क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कनेक्टिविटी के लिए भी परिणामोन्मुखी कार्य किए हैं।

श्री पटेल ने जोड़ा कि पानी विकास का मुख्य आधार है। आज इंजीनियरिंग कौशल से हम उकाई बांध का पानी पहाड़ी क्षेत्रों में पहुँचा रहे हैं। सोनगढ, उच्छल तथा नीझर उद्वहन सिंचाई योजना और बोरीसावर उद्वहन सिंचाई योजना से हजारों किसानों को बारहों महीने पानी मिलेगा तथा उनकी खेती समृद्ध होगी।

उच्छल तहसील के बाबरघाट में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के आदिजाति विकास मंत्री तथा तापी जिला प्रभारी श्री नरेशभाई पटेल ने कहा कि तापी मैया दक्षिण गुजरात के लिए जीवनदायिनी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उकेरे गए विकास के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने जोड़ा कि जन कल्याण तथा ढाँचागत सुविधाओं के निर्माण द्वारा राज्य सरकार सुदूरवर्ती नागरिकों तक सुख-सुविधाएँ पहुँचाने को कटिबद्ध है।

उन्होंने किसानों को दोनों उद्वहन सिंचाई योजनाओं का लाभ लेने के साथ ड्रिप इरीगेशन पर मिलने वाली सब्सिडी का भी लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर जल संसाधन तथा जलापूर्ति राज्य मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल ने गुजरात के सुचारु जल प्रबंधन का विवरण देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से लोकार्पित 962.12 करोड़ रुपए की उकाई जलाशय योजना आधारित सोनगढ, उच्छ, नीझर उद्वहन सिंचाई योजना से सोनगढ, उच्छल, नीझर तथा कुकरमुंडा के 136 गाँवों की 28 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही; 651.37 करोड़ रुपए की लागत से साकार हो रही बोरीसावर योजना द्वारा सोनगढ एवं व्यारा तहसीलों के 29 गाँवों की 8 हेक्टेयर से अधिक भूमि भी सिंचाई सुविधा से सज्ज होगी।

खेल, उद्योग तथा पर्यटन राज्य मंत्री डॉ. जयरामभाई गामित ने भी आदिवासी क्षेत्र तथा आदिवासी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के कामकाज की प्रशंसा की।

कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने दो उद्घाटित बहुमूल्य योजनाओं तथा किसानों की समृद्धि की झाँकी दर्शाने वाली लघु फिल्म देखी।

इस अवसर पर उच्छल तहसील के बाबरघाट में मंत्रियों सर्वश्री नरेशभाई पटेल, ईश्वरसिंह पटेल तथा जयरामभाई गामित ने कार्यक्रम स्थल पर तापी मैया के नीर का स्वागत-सत्कार किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जालमसिंह वसावा, जिले के अग्रणी श्री सूरजभाई वसावा, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री पी. सी. व्यास, जिला कलेक्टर डॉ. विपिन गर्ग, विधायक श्री मोहनभाई कोंकणी सहित उच्चाधिकारी, पदाधिकारी, अग्रणी, आमंत्रित, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन-किसान उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं को गति देने का महत्वपूर्ण निर्णय

वनबंधु कल्याण योजना के तहत आदिवासी गांवों के स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने के कार्यों और स्ट्रक्चर निर्माण के लिए 362 करोड़ रुपए के कार्यों को दी मंजूरी

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के अंबाजी से लेकर उमरगाम तक के समग्र आदिवासी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हुए गांवों तक आधारभूत सुविधाओं को और भी सुलभ बनाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में आदिवासी क्षेत्रों के गांवों के स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए 325.81 किमी लंबाई के कार्यों तथा स्ट्रक्चर निर्माण के कार्यों सहित 293 कार्यों के लिए कुल 362.57 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई वनबंधु कल्याण योजना के अंतर्गत आदिवासी समुदायों तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाएं आसानी से और समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने इन कार्यों को मंजूर किया है।

आदिवासी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण होने से विद्यार्थियों को स्कूल तक पहुंचने में आसानी होगी।

इतना ही नहीं, आकस्मिक परिस्थिति में मरीजों को निकट स्थित स्वास्थ्य केंद्र तक तेजी से पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की इस पहल से आदिवासी क्षेत्रों में विकास के नए द्वार खुलने से 'सबका साथ, सबका विकास' का ध्येय भी साकार होगा।

असारवा – खेड़ब्रह्मा के बीच 01 अप्रैल से नई मेमू ट्रेन सेवा का नियमित संचालन

यात्रियों की सुविधा एवं क्षेत्रीय संपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिनांक 31 मार्च 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेड़ब्रह्मा रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद (असारवा) के बीच नई रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे।

v प्रारंभिक ट्रेन सेवा (Inaugural Run)

दिनांक 31 मार्च 2026 को ट्रेन संख्या 09439 खेड़ब्रह्मा–असारवा मेमू (one way) खेड़ब्रह्मा से 16:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा 19:45 बजे असारवा पहुचेंगी।

v नियमित ट्रेन सेवा

ट्रेन संख्या 69251 असारवा–खेड़ब्रह्मा मेमू दिनांक 01 अप्रैल 2026 (बुधवार) से सप्ताह के सभी दिनों में असारवा से सायं 18:25 बजे प्रस्थान कर 21:10 बजे खेड़ब्रह्मा पहुँचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 69252 खेड़ब्रह्मा–असारवा मेमू दिनांक 02 अप्रैल 2026 (गुरुवार) से सप्ताह के सभी दिनों में खेड़ब्रह्मा से प्रातः 06:45 बजे प्रस्थान कर 09:30 बजे असारवा पहुँचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन सरदारग्राम, नरोडा, डभोड़ा, नांदोल दहेगाम, रखियाल, तालोद, प्रांतिज, सोनासन, हिम्मतनगर एवं इडर रेलवे स्टेशनों पर ठहरेगी।

यह ट्रेन 08 कोच की मेमू रेक के साथ संचालित की जाएगी।

ट्रेनों के ठहराव, समय एवं कोच संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

पश्चिम रेलवे द्वारा गंगाधरा में प्रथम ग्रीनफील्ड,गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ,मुंबई मंडल ने रिकॉर्ड 8 माह में किया निर्माण; सूरत के औद्योगिक लॉजिस्टिक्स को मिलेगा बढ़ावा

पश्चिम रेलवे ने 30 मार्च, 2026 को मुंबई सेंट्रल मंडल के अंतर्गत गंगाधरा में रेलवे भूमि पर अपने पहले ग्रीनफील्ड गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (GCT) का सफलतापूर्वक शुभारंभ कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस टर्मिनल का उद्घाटन पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार द्वारा किया गया, जिन्होंने इस अवसर पर पहली कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर परिचालन का शुभारंभ भी किया।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस टर्मिनल का विकास मेसर्स प्रिस्टीन कनेरिया लॉजिस्टिक्स पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसे मात्र 8 महीनों के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है, जो भारतीय रेल पर अब तक का सबसे तेजी से निर्मित गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है।

यह अत्याधुनिक टर्मिनल लगभग 44,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला पूर्णतः रेलवे भूमि पर विकसित किया गया है और सूरत के औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है। यह टर्मिनल स्टील, वस्त्र, सीमेंट, फ्लाई ऐश, रसायन तथा उर्वरक सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के प्रबंधन में सक्षम होगा, जिससे माल लदान में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा ग्राहकों को कुशल और प्रभावी लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्राप्त होंगी। इस टर्मिनल के शुरू होने से पश्चिम रेलवे के माल परिवहन क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सड़क से रेल की ओर निर्बाध परिवहन को प्रोत्साहित करते हुए यह टर्मिनल सड़क यातायात में कमी लाएगा, कार्बन उत्सर्जन घटाएगा तथा पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा। साथ ही, मालगाड़ियों के तेज आवागमन और त्वरित टर्नअराउंड से परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी, जिससे माल एवं यात्री दोनों सेवाओं के लिए एक सुदृढ़ और उच्च गति वाले रेल नेटवर्क के विकास को बल मिलेगा।

यह उपलब्धि पश्चिम रेलवे की अवसंरचना विकास, ग्राहक-केंद्रित सेवाओं तथा भारत सरकार के गति शक्ति विजन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पश्चिम रेलवे इस प्रकार की पहलों के माध्यम से सतत, कुशल एवं भविष्य के अनुरूप परिवहन समाधान प्रदान करते हुए देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देती रहेगी।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विवाद: लाखों नाम गायब, न्यायाधिकरण का गठन अभी बाकी है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। पश्चिम बंगाल में चुनाव बस कुछ ही दिनों के भीतर होने वाले हैं, और मतदाता सूची को लेकर हर दिन नए गुट उभर रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में यह दावा किया गया था कि मतदाता सूची सुधार के बाद प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी, लेकिन शंकाएं दूर होने के बजाय स्थिति और भी जटिल हो गई है। पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, बीएलओ, डॉक्टरों, वकीलों और पुलिसकर्मियों के नाम मतदाता सूची से गायब होने की खबरें आ रही हैं। ये वे लोग हैं जिनके नाम विचाराधीन थे। हालांकि विवाद के बाद पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नाम हटाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है, क्या अन्य मामलों में भी यही स्थिति है? क्या जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें न्यायाधिकरण में सुनवाई मिल रही है? यदि न्यायाधिकरण का गठन अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या लाखों लोग मतदाता सूची और मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रह जाएंगे? राज्य में विचाराधीन मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए जाने के कारण ये सवाल उठ रहे हैं। राज्य में कुल 60 लाख से अधिक मामलों की जांच चल रही है। 705 न्यायिक अधिकारियों की एक टीम अब तक 37 लाख मामलों का फैसला कर चुकी है। दो पूरक सूचियां जारी की जा चुकी हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि अब तक कितने नाम हटाए गए हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राज्य भर में 15 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। राज्य में सबसे अधिक मामले मुर्शिदाबाद में 11 लाख और मालदा में 8.28 लाख दर्ज किए गए हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में डॉक्टरों, वकीलों, पुलिस अधिकारियों, बीएसएफ कर्मियों, प्रोफेसरों और आम किसानों और मजदूरों के नाम भी मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। प्रभावित लोगों का दावा है कि वे पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। लेकिन सबूत पेश करने के बावजूद उनके नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़े गए हैं। खबरों के मुताबिक, फार्मासिस्ट खैरुल आलम कहते हैं, "मेरे दो भाई और एक बहन डॉक्टर हैं। एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और एक इंटर्नशिप कर रहे हैं।" हमने अपने डॉक्टर पंजीकरण प्रमाण पत्र, माध्यमिक प्रवेश पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और 2002 के पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा किए थे। फिर भी, दोनों डॉक्टरों के नाम हटा दिए गए। उनकी बहन, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में स्त्री रोग विशेषज्ञ खालिदा खातून कहती हैं, "मैंने सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे। अब मैं मतदाता नहीं हूं। कोई कारण नहीं बताया गया है। मैं इसे न्यायाधिकरण में चुनौती दूंगी।" हमारे नाम अब क्यों हटाए गए हैं जबकि हमारे दादा और परदादा 1952 की मतदाता सूची में थे? इन सभी अनसुलझे सवालों के जवाब न्यायाधिकरण के गठन के बाद ही मिलेंगे। यहाँ अभी तक न्यायाधिकरण का गठन नहीं हुआ है। फिर वे अपील कैसे करेंगे? "ये है नया भारत का सम्पा"।

वडोदरा - नागदा सेक्शन पर 'कवच 4.0' का सफलतापूर्वक कमीशन, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने कवच प्रणाली से सज्ज स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

मुंबई - नई दिल्ली मुख्य मार्ग का अधिकतम रुट अब कवच प्रणाली से सज्ज पश्चिम रेलवे द्वारा रेल परिचालन में संरक्षा को और मजबूत करने के क्रम में 30 मार्च, 2026 को वडोदरा - नागदा सेक्शन पर कवच 4.0 सिस्टम को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया। इस अवसर पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार द्वारा वडोदरा स्टेशन से कवच से सज्ज स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गयी। इस प्रकार मिशन रफ़्तार के अंतर्गत मुंबई - नई दिल्ली मुख्य मार्ग के पश्चिम रेलवे के निर्धारित 693 रुट किलोमीटर में से 559.5 रुट किलोमीटर पर यानी अधिकतम रुट पर इस प्रणाली को स्थापित किया जा चुका है। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार ने इस अवसर पर बताया कि वडोदरा - नागदा सेक्शन के अंतर्गत वडोदरा से मंगल महुडी सेक्शन (122.5 Rkm) और पंचपिपलिया - नागदा (102.01 Rkm) सेक्शन के बीच में यानी कुल 224.51रुट किलोमीटर पर कवच प्रणाली को आज सफलतापूर्वक लांच किया गया है। मंगल महुडी से पंचपिपलिया के बीच इस प्रणाली को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है और जल्द ही इसे आटोमेटिक सिगनलिंग के साथ पूरा कर लिया जायेगा। रेलवे द्वारा इस वित्तीय वर्ष 2025 -26 में कुल 659.5 रुट किलोमीटर पर कवच प्रणाली स्थापित की गयी है। वडोदरा मंडल द्वारा इससे पहले जनवरी 2026 में वडोदरा - विरार सेक्शन पर कवच सिस्टम चालू किया गया था और आज वडोदरा से गोधरा होते हुए नागदा तक इसे कमीशन किया गया है। कवच एक ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है और यह मानवीय गलतियों के जोखिम को कम करने के लिए ट्रेन सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है। जो कि मानवीय त्रुटि के कारण 'सिग्नल पासिंग एट डेंजर' (SPAD) से होने वाले परिणामों को रोकती है।

वडोदरा–नागदा सेक्शन पर इस जटिल कार्य के निष्पादन हेतु प्रत्येक स्टेशन तथा प्रत्येक एब्सोल्यूट/ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सेक्शन के लिए पृथक योजना तैयार की गई, पटरियों पर 6000 से अधिक स्थानों पर RFID टैग का प्रोग्रामिंग एवं स्थापना कार्य किया गया, 26 स्टेशनों, 13 मध्य-खंडों तथा लोकोमोटिव के बीच सतत रेडियो संचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, प्रत्येक स्टेशन पर कुल 39 रेडियो संचार टावर एवं आवश्यक उपकरण स्थापित किए गए, पूरे मार्ग पर UP एवं DN दोनों दिशाओं में लगभग 600 किमी लंबाई की OFC केबल बिछाई गई, साथ ही प्रत्येक स्टेशन, मध्य-खंड एवं LC गेट पर आधुनिक 'कवच' उपकरण स्थापित कर उन्हें मौजूदा सिग्नलिंग प्रणाली से एकीकृत किया गया, लोकोमोटिव में भी 'कवच' उपकरण लगाए गए तथा अंततः संपूर्ण प्रणाली का सफलतापूर्वक ट्रायल एवं परीक्षण किया गया।

'कवच' प्रणाली अपने यूरोपीय समकक्षों (ETCS) की तुलना में बहुत सस्ती है। अभी तक WAP-7, WAG9, WAP5 लोकोमोटिव में कवच प्रणाली लगाई गयी है। जल्द ही, इसे दूसरे लोकोमोटिव पर भी शुरू किया जाएगा। अब तक पश्चिम रेलवे पर कुल 364 लोकोमोटिव में 'कवच' प्रणाली लगाई जा चुकी है।

पश्चिम रेलवे आधुनिक एवं स्वदेशी तकनीकों को अपनाकर सुरक्षित, दक्ष एवं भविष्य उन्मुख रेल नेटवर्क के निर्माण हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

सूरत में भूमि माफिया और वकील-बिल्डर सिंडिकेट के खिलाफ गंभीर आरोप

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। गुजरात का मिनी इंडिया कहे जाने वाला सूरत, विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ हर प्रांत से लोग आकर शहर के अलग-अलग हिस्सों में बसने लगे, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई, ज़मीन की कीमतें बढ़ने लगीं और इसका फायदा उठाते हुए कुछ बड़े बिल्डर महाकाल ग्रुप के उन वकीलों के ज़रिए करोड़ों रुपये की ज़मीनें बिकवा रहे हैं जो अदालतों में वकालत नहीं करते। आज भी, बुजुर्ग वकील गुज़ारा करने के लिए व्हीलचेयर पर बैठकर वकालत करने को मजबूर हैं। जीवन भर वकालत करने के बावजूद वे मुश्किल से एक घर, एक छोटा दफ्तर या एक चारपहिया वाहन ही खरीद पाए हैं। दूसरी ओर, कुछ वकील सर्टिफिकेट लेने के बाद भी अदालत में कभी पेश नहीं हुए, लेकिन वे अपने वकील के ज़रिए तभी केस दर्ज कराते हैं जब जजों की बेंच किसी जज के साथ आती है। इस तरह, ऐसे वकील घर बनवाकर आलीशान दफ्तर, महंगी गाड़ियाँ और बंगले बना लेते हैं। ये वकील अपने दफ्तरों में बैठकर बड़े-बड़े केस निपटाते हैं। इनके दफ्तरों में तथाकथित अहंकारी और कुख्यात असामाजिक तत्व पनाह लेते हैं। कृषि व्यवसाय में लगे बड़े किसानों के खिलाफ अत्याचार और अन्य मामलों में ऐसे वकील पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें जेल भेज चुके हैं। शहर के बड़े बिल्डर सुबह-शाम ऐसे वकीलों को अपने यहाँ बुलाते हैं। किसानों के साथ जमीन के मामलों में उन्हें असामाजिक तत्वों या पुलिस से फोन आते हैं और उन्हें धमकाया जाता है। सालों से वकालत कर रहे वकीलों के पास आलीशान दफ्तर नहीं होते। वहीं, ऐसे उपद्रवी वकील जो अदालतों में वकालत नहीं करते, उनके पास आलीशान दफ्तर होते हैं। और बिना वकालत किए ये वकील मौज-मस्ती करते हैं। उनके बड़े-बड़े फार्महाउसों में बड़ी-बड़ी पार्टियां होती हैं। इन पार्टियों में बड़े-बड़े आईपीएस और आईएएस अधिकारी मौजूद रहते हैं। नेताओं के आशीर्वाद से शहर में महाकाल ग्रुप नाम का एक गिरोह बना है जो राजस्व अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की तैनाती तय करता है। इस गिरोह के ज्यादातर सदस्य कट्टरपंथी हैं। इस गिरोह के सदस्य आयकर विभाग के छापे मारते हैं, जिनके बिल्डरों या उद्योगपतियों के यहाँ या तो छापेमारी होती है या उन्हें वहाँ बसाया जाता है। उनके अधीन राजस्व विभाग के अधिकारियों का तबादला नेताओं के आशीर्वाद से सूरत शहर में कर दिया जाता है। करोड़ों रुपये की जमीनें ऐसे वकीलों द्वारा कीमत तय करके, कट्टरपंथियों की मदद से और धमकाकर हड़प ली जाती हैं। फिलहाल, महाकाल समूह के चार हाथ मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्रियों पर हैं। यह स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय है। सूरत के राजुगीजू अल्थान गांव के एक बड़े किसान के खिलाफ उनकी 73AA जमीन को लेकर अत्याचार का मामला दर्ज किया गया और उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया गया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के कारण बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। अगर बड़े किसानों के साथ ऐसा हो रहा है, तो सूरत जिले के तथाकथित छोटे किसानों के फार्महाउस वास्तव में असामाजिक तत्वों के कब्जे में हैं। और वहीं से बिल्डरों को संरक्षण मिलता है। कपड़ा और हीरा उद्योग में गबन करने वालों को उनके गिरोह द्वारा संरक्षण दिया जाता है। बिल्डर भी उन्हें संरक्षण देते हैं ताकि उन्हें बाजार से लिया गया पैसा वापस न करना पड़े। पुलिस से बचाने के लिए उन्हें फार्महाउसों में पनाह दी जाती है। और पुलिस भी इसमें शामिल है। तत्कालीन अधिकारियों ने अत्याचार के मामलों की आड़ में राजुगीजू से करोड़ों रुपये लूटे। महाकाल समूह का एक सिंडिकेट बनाया गया था, जिसमें सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों, असामाजिक तत्वों, वकीलों और लाइसेंसधारियों सहित 25 से 30 लोगों का समूह था। ये वकील खुद वकालत नहीं करते और तय करते हैं कि किस मामले को किस न्यायाधीश की पीठ में ले जाना है। और अगर उनके वकील भरोसेमंद हैं और जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जिस भी न्यायाधीश की पीठ में मामला जाता है, उसमें जीत जाते हैं, तो ऐसे वकील बिना किसी तरह की वकालत किए करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इसलिए, अगर ऐसे वकील वास्तव में वकालत नहीं कर रहे हैं, तो उनके नाम बार काउंसिल से हटा दिए जाने चाहिए। वे एसी दफ्तरों में बैठकर अपने पक्ष में मामले लड़ रहे हैं। और ये लोग केस जीतने का वादा करके पैसे ले रहे हैं। ऐसे वकीलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही, उनके दफ्तरों की मेजों पर पड़ी बेकार फाइलों की भी जांच होनी चाहिए। महाकाल समूह के सदस्यों की छोटी से छोटी जानकारी जुटाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जब कुछ पुलिस अधिकारी और राजस्व अधिकारी तबादलों के बाद आते हैं, तो महाकाल समूह उनके परिवार के आने तक उन्हें भोजन और आवास मुहैया कराता है। महाकाल समूह में भी काम का बंटवारा अलग-अलग सदस्यों के बीच है, जिनमें से कुछ कर्मचारी/अधिकारियों के तबादलों में शामिल हैं। इसके अलावा, इस महाकाल समूह की सूचना पर आयकर विभाग के छापे आदि भी चलाए जाते हैं। इन सभी का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा।